>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Administrators-General (Amendment) Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha (Discussion concluded and Bill passed).

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Administrators-General Act, 1963, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

...(*Interruptions*) Sir, I appreciate that. ...(*Interruptions*) Sir, I must say that the positive approach, the outreach and cooperation of the Opposition is to be greatly welcomed, applauded and recognized.

Sir, in the matter of helping the poor and the disadvantaged people, this attitude is very good. ...(*Interruptions*) Sir, I will just put it on record that the objective of Section 29 of the Act is essentially to empower the Administrator-General to grant certificates to any person who is interested in the property of a deceased person without being a creditor so that on the basis of that certificate, the assets that have been left behind by the deceased person, which do not exceed in value of a very large amount, can be administered and looked after by the person given the certificate.

The Act was originally enacted in 1963. At that time, the monetary limit was only Rs.5,000. It was subsequently raised to Rs.15,000 in 1972; Rs.50,000 in 1983 and to Rs. 2 lakh in 1999. So, the monetary limit has been raised from time to time looking at the economic circumstances and the value of properties that are often left behind.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, इस बिल पर डिसकशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह राज्य सभा से पास हो गया है। इसे बिना बहस के पास कर दीजिए।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): इस बिल को बिना बहस के पास कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री सलमान खुर्शीद: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यही सकारात्मक सहयोग हर मामले में मिलता रहेगा तो हम काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा माननीय सांसदों से निवेदन है कि इस बिल को पारित करें। हम सब साथ मिलकर बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम उठाएंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): हाउस की सर्वसम्मति से पास करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस की सहमति है तो बिना बहस के इस बिल को पास कर दें।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Administrators-General Act, 1963, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section

9, 10, 29 and 36 of Act 45 of 1963

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

...(*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने के लिए सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, यह बिल कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम कमेटी में थे। दो लाख से दस लाख कर रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहना है कि यह मेंडेटरी क्यों नहीं है? अभी भी 28 में से 24 राज्यों ने इस पर टिप्पणी की है, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम में यह अधिनियम प्रवृत्ति में ही नहीं है। मेरा एक ही प्वाइंट है कि इसे मेंडेटरी किया जाना चाहिए ताकि जितनी विधवाएं और नाबालिग हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सके।

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, the Bill is applicable to the entire country but the exceptions in all our legislation are laid for Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Assembly then takes up all beneficial Bills that are passed by the Parliament. So, it is not possible for me to make a commitment on that.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सिक्किम भी है।

SHRI SALMAN KHURSHEED: But, as far as we are concerned, the Assemblies will do whatever is in the interest of the poor people of their States. I am sure that the wishes of the hon. Member will be heard and I am sure that the wishes of the hon. Member will be factored in.

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमें भी एक मिनट बोलने का मौका चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब ने ही तो कहा है कि बहस नहीं होनी चाहिए। बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब ने ही तो कहा है कि बिना बहस के बिल पास करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

*m04

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आए हैं, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप तो समर्थन कर रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप सब ने ही तो कहा है कि बिना बहस के बिल पास करना है। वह कुछ प्वाइंट बता रहे थे।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed. "

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.